



2 February, 2024

अंतरिम बजट 2024 की मुख्य बातें

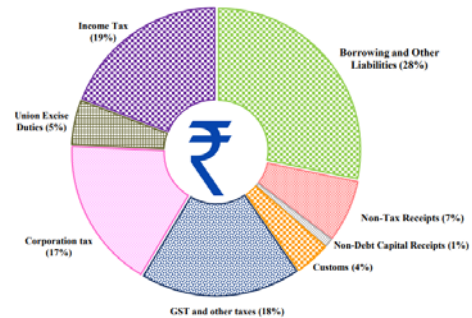
संदर्भ: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2024 के लिए अंतरिम बजट पेश किया।

अंतरिम बजट 2024 की मुख्य बातें:

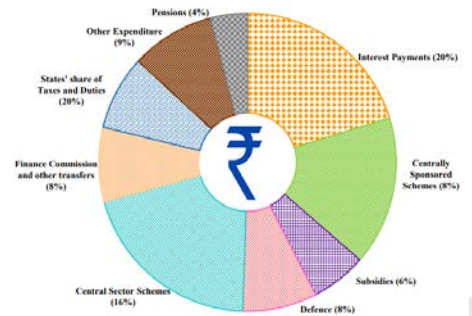
- वास्तविक जीडीपी वृद्धि और राजकोषीय अनुमान:**
 - वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की वास्तविक जीडीपी 7.3% बढ़ने का अनुमान है।
 - वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.1% है।
 - 2014 और 2023 के बीच प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रवाह 596 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो 2005 और 2014 के बीच दर्ज किए गए प्रवाह से दोगुना है।
- प्राथमिकता वाले क्षेत्र और वित्तीय आवंटन:**
 - इस बजट में 'गरीब', 'महिलाएं', 'युवा', और 'अन्नदाता' (किसान) जैसे हाशिए पर रहने वाले वर्गों का उत्थान सर्वोच्च प्राथमिकता वाला क्षेत्र है।
 - पूँजीगत व्यय परिव्यय में 11.1% की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो 11,11,111 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।
 - राज्यों को पूँजीगत व्यय के लिए पचास वर्षों के ब्याज मुक्त ऋण की पेशकश करने वाली योजना 1.3 लाख करोड़ रुपये के आवंटित परिव्यय के साथ जारी रहेगी।
- सामाजिक न्याय पहल:**
 - एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक में बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले 25 करोड़ लोगों तक सरकारी सहायता पहुंची है।
 - पीएम-जन धन खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से 34 लाख करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं, जिससे सरकार को पर्याप्त बचत हुई है।
 - पीएम-स्वनिधि, पीएम-जनमन योजना और पीएम-विश्वकर्मा योजना जैसे विभिन्न सहायता कार्यक्रम समाज के विभिन्न वर्गों की सहायता कर रहे हैं।
- किसानों का कल्याण:**
 - पीएम-किसान सम्मान योजना के कार्यान्वयन से 11.8 करोड़ किसानों को सीधे लाभ हुआ है।
 - फसल बीमा के लिए पीएम फसल बीमा योजना के तहत कुल 4 करोड़ किसानों को कवर किया गया है।
 - इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम) के तहत 1361 मंडियों के एकीकरण से देश भर में 1.8 करोड़ किसानों के लिए व्यापार की सुविधा प्राप्त हुई है।
- महिलाओं का सशक्तिकरण:**
 - महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण के प्रावधान ने उनके आर्थिक सशक्तिकरण को काफी बढ़ावा दिया है।
 - उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महिला नामांकन में 28% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
 - 70% से अधिक ग्रामीण महिलाओं को पीएम आवास योजना जैसी आवास योजनाओं में शामिल किया गया है, जो महिला कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- आवास और ऊर्जा पहल:**
 - कोविड की चुनौतियों के बावजूद, सरकार सभी के लिए आवास सुनिश्चित करने के लिए पीएम आवास योजना (ग्रामीण) पर कार्य कर रही है।
 - ऊर्जा लागत को कम करने और नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, रूफटॉप सोलरइजेशन के माध्यम से 1 करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करने की योजना पर काम चल रहा है।
 - आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को शामिल करने के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य देखभाल कवरेज का विस्तार किया जा रहा है, जिससे सभी के लिए स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच सुनिश्चित हो सके।
- कृषि एवं बुनियादी ढांचा विकास:**
 - प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना को औपचारिक बनाने जैसी योजनाओं की सफलता ने कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों को बढ़ावा दिया गया है।

- विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धि और विकास को उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से अनुसंधान और नवाचार को वित्तपोषित करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये के एक कोष की स्थापना की जा रही है।
- सरकार बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पूँजीगत व्यय परिव्यय में 11.1% की वृद्धि कर रही है, जो बुनियादी ढांचे के विकास और रोजगार सृजन के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता का संकेत है।

Rupee Comes From



Rupee Goes To



रेलवे, विमानन और हरित ऊर्जा:

- पीएम गति शक्ति पहल के तहत, रसद दक्षता में सुधार और लागत कम करने के लिए तीन प्रमुख आर्थिक रेलवे गलियारा कार्यक्रमों की पहचान की गई है।
- देश में हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी होकर 149 हो गई है, जिससे हवाई कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास में वृद्धि हुई है।
- कोयला गैसीकरण, द्रवीकरण क्षमता और संपीड़ित बायोगैस के अनिवार्य मिश्रण के लिए योजनाएं चल रही हैं, जो हरित ऊर्जा पहल के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देती हैं।

पर्यटन और निवेश प्रोत्साहन:

- राज्यों को वैश्विक स्तर पर ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर ध्यान देने के साथ प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों को व्यापक रूप से विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सुविधाओं और सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर पर्यटक केंद्रों की रेटिंग के लिए एक रूपरेखा स्थापित की जा रही है।
- पर्यटन क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करते हुए पर्यटन विकास के लिए राज्यों को दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा।

कर सुधार और सेवा संवर्द्धन:

- सरकार ने करदाताओं को स्थिरता और पूर्वानुमान प्रदान करते हुए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों दोनों के लिए समान कर दरों को बनाए रखने का निर्णय लिया है।
- पिछले दशक में प्रत्यक्ष कर संग्रह तीन गुना हो गया है, जो कर प्रशासन और अनुपालन में सुधार को दर्शाता है।
- कुछ आय वर्गों के लिए कर देनदारी कम कर दी गई है और सीमा शुल्क सुधारों के कारण आयात जारी करने का समय कम हो गया है, जिससे व्यापार और आर्थिक विकास में आसानी हुई है।

Face to Face Centres





2 February, 2024

आर्थिक प्रगति और शासन:

- वर्ष 2014 के बाद से हुई प्रगति को दर्शाते हुए, सरकार आर्थिक विकास, शासन और सुधारों में महत्वपूर्ण प्रगति को स्वीकार करती है।
- सरकार देश की आर्थिक यात्रा पर एक श्वेत पत्र तैयार करने, शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

MQ-9B मानव रहित हवाई वाहन

संदर्भ: हाल ही में, अमेरिकी कांग्रेस ने भारत को 31 एमक्यू-9बी; उच्च ऊंचाई वाले लंबे समय तक चलने वाले सशस्त्र मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) की संभावित बिक्री के बारे में सूचित किया है।

भारत में MQ-9B UAV की संभावित बिक्री:

- अमेरिकी कांग्रेस को औपचारिक रूप से विगत 1 फरवरी को भारत को 31 एमक्यू-9बी उच्च ऊंचाई वाले लंबे समय तक चलने वाले सशस्त्र मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) की संभावित बिक्री के बारे में सूचित किया गया।
- कथित तौर पर पन्नू प्रकरण (Pannun episode) की घटना ने; भारत की "उच्च-स्तरीय" जांच के कारण अमेरिकी कांग्रेस ने सौदे पर रोक लगा दी।
- रक्षा सहयोग एजेंसी (डीएससीए) ने एक विज्ञप्ति जारी कर संभावित विदेशी सैन्य बिक्री के लिए राज्य विभाग की मंजूरी की पुष्टि की, जिसका अनुमान \$3.99 बिलियन है।
- भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रस्ताव और स्वीकृति पत्र (एलओए) के साथ बिक्री समाप्त करने से पहले कांग्रेस के पास प्रस्तावित बिक्री की समीक्षा करने के लिए 30 दिन का समय है।

प्रस्तावित बिक्री का विवरण:

- प्रस्तावित बिक्री में 170 AGM-114R हेलफायर मिसाइलें, 16 M36E9 हेलफायर कैप्टिव एयर ट्रेनिंग मिसाइलें, 310 GBU-39B/B लेजर स्मॉल डायमीटर बम (SDB), और 08 GBU-39B/B LSDB निर्देशित परीक्षण वाहन लाइव फ़्लूज के साथ अन्य संबंधित उपकरण शामिल हैं।
- इस सौदे का उद्देश्य अमेरिका-भारत के रणनीतिक संबंधों को मजबूत करना और भारत-प्रशांत और दक्षिण एशिया क्षेत्र में एक प्रमुख रक्षा भागीदार भारत की सुरक्षा को बढ़ाना है।

ऑफसेट और सामान्य परमाणु समझौता की भूमिका:

- भारत आमतौर पर ऐसे सौदों में ऑफसेट का अनुरोध करता है, और किसी भी ऑफसेट समझौते को भारत और जनरल एटॉमिक्स (सामान्य परमाणु) के बीच बातचीत में परिभाषित किया जाएगा।
- जनरल एटॉमिक्स (सामान्य परमाणु) ने; सौदे के हिस्से के रूप में भारत में एक वैश्विक रखरखाव, मरम्मत और ओवरऑल (एमआरओ) सुविधा स्थापित करने की योजना बनाई है, जिसे ऑफसेट दायित्वों में गिना जाएगा।

खरीद प्रक्रिया और समयेखा:

- रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने 15 जून, 2023 को जनरल एटॉमिक्स से 31 एमक्यू-9बी यूएवी की खरीद को मंजूरी दे दी है।
- G20 शिखर सम्मेलन में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के बीच वार्ता से ठीक पहले अमेरिकी सरकार को अनुरोध पत्र जारी किया गया था।
- रक्षा अधिकारियों का अनुमान है कि सौदा इस वर्ष पूरा हो जाएगा, अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के तीन साल बाद डिलीवरी शुरू हो जाएगी।

उन्नत क्षमताएं और सहयोग:

- एमक्यू-9बी यूएवी भारतीय सशस्त्र बलों की खुफिया, निगरानी और टोही (आईएसआर) क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि करेगा।
- अमेरिकी मूल के P-8I लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान के साथ सहयोग से हिंद महासागर क्षेत्र पर भारतीय नौसेना की निगरानी मजबूत होगी।

Multi-rotor Drones (multi-copters)



Have multiple rotors



Take off and land vertically



Use lithium polymer batteries



Used for aerial photography and videography

Single-rotor Drones



Take off and land vertically



More energy efficient than multi-copters due to their single rotor



Can carry heavier payloads and cover greater distances than multi-copters



Can use gasoline engines instead of a battery

Fixed-wing Drones



Take off and land at an angle to the ground (similar to airplanes)



More energy efficient than single or multi-rotor drones due to their wings providing lift



Can remain airborne for several hours



Used for long-distance delivery missions or mapping



Can use gasoline engines instead of a battery

NEWS IN BETWEEN THE LINES

अमृत उद्यान



राष्ट्रपति भवन (दिल्ली) में अमृत उद्यान (पहले मुगल गार्डन) उत्सव-1 के तहत यह आम जनता के लिए 2 फरवरी से 31 मार्च खुला रहेगा।

अमृत उद्यान के बारे में:

- भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष (2023) पूरे होने के उपलक्ष्य में दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन (राष्ट्रपति आवास) के मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया था।
- यह उद्यान 15 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें मुगल और अंग्रेजी दोनों तरह की भूमिर्माण शैलियाँ हैं।
- बगीचों के डिजाइन को 1917 में एडविन लुटियंस और बागवानी निदेशक विलियम मस्टो द्वारा अंतिम रूप दिया गया था।
- बगीचे का डिजाइन आगरा में ताज महल, दिल्ली में हुमायूँ का मकबरा और कश्मीर में निशात बाग और भारत और फारस के लघु चित्रों से प्रेरित था।

Face to Face Centres





2 February, 2024

सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला



भारत की राष्ट्रपति (श्रीमती द्रौपदी मुर्मू) 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2024 का उद्घाटन करने के लिए आज सूरजकुंड (हरियाणा) का दौरा करेंगी।

सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के बारे में:

- "सूरजकुंड" नाम का अर्थ 'सूर्य की झील' है जो इसके आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक महत्व को दर्शाता है।
- यह एक प्राचीन जलाशय है और कहा जाता है कि इसे 10वीं शताब्दी में तोमर वंश के राजा सूरजपाल ने बनवाया था।
- इस वर्ष गुजरात थीम राज्य है जो क्षेत्र के विभिन्न कला रूपों और हस्तशिल्प के माध्यम से अपनी अनूठी संस्कृति और समृद्ध विरासत का प्रदर्शन कर रहा है।
- इथियोपिया, घाना, केन्या, नामीबिया, नाइजीरिया, युगांडा, जिम्बाब्वे, मॉरीशस, म्यांमार, नेपाल, रूस, श्रीलंका सहित लगभग 50 देश मेले में भाग लेंगे।
- इसे दुनिया के सबसे बड़े शिल्प मेलों में से एक माना जाता है और 1987 से इसका आयोजन किया जा रहा है।
- मेले का आयोजन केंद्रीय पर्यटन और कपड़ा मंत्रालय के साथ-साथ सांस्कृतिक मंत्रालय, सूरजकुंड मेला प्राधिकरण और हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से संयुक्त रूप से किया जाता है।

अंत्योदय अन्न योजना



हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वितरण योजना (पीडीएस) के माध्यम से वितरित अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों के लिए चीनी सब्सिडी योजना को दो और वर्षों के लिए (मार्च 2026 तक) बढ़ाने को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

अंत्योदय अन्न योजना के बारे में:

- अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना है जो खाद्य सुरक्षा प्रदान करती है और इसका उद्देश्य भारत में भूख को समाप्त करना है।
- यह योजना केंद्र सरकार द्वारा 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई थी और सबसे पहले राजस्थान में लागू की गई थी।
- सितंबर 2013 में, संसद ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 अधिनियमित किया।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली:

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) भारत में एक खाद्य सुरक्षा प्रणाली है जो गरीबों को सब्सिडी वाले खाद्य और गैर-खाद्य पदार्थ प्रदान करती है।
- उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने पीडीएस की स्थापना की।
- यह गरीबों को सरकार द्वारा विनियमित राशन की दुकानों से खाद्यान्न खरीदने की अनुमति देता है और गेहूं, चावल, चीनी और मिट्टी के तेल जैसी प्रमुख वस्तुओं का वितरण करता है।
- भारतीय खाद्य निगम (FCI) राशन की दुकानों पर खाद्यान्न की आपूर्ति करता है।
- लाभार्थियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है: गरीबी रेखा से नीचे के परिवार और गरीबी रेखा से ऊपर के परिवार।

राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन



हाल ही में केंद्रीय बजट 2024-25 में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की घोषणा ना होने पर पर वैज्ञानिकों ने निराशा व्यक्त की है।

नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बारे में:

- नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एनआरएफ) भारत में एक प्रस्तावित निकाय है।
- पहली बार 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के तहत प्रस्तावित एनआरएफ का लक्ष्य देश में वैज्ञानिक अनुसंधान निधि को केंद्रीकृत करना है।
- यह वर्तमान में स्थापित सरकारी फंडिंग एजेंसियों जैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का स्थान लेगा।
- इसकी अध्यक्षता प्रधान मंत्री करेंगे और इसमें 10 निदेशालय होंगे जो विज्ञान, कला, मानविकी, नवाचार और उद्यमिता के विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
- प्रधान मंत्री पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा शिक्षा मंत्री पदेन उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।
- यह एक नीतिगत ढांचा और नियामक प्रक्रियाएं बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा जो अनुसंधान एवं विकास पर उद्योग द्वारा सहयोग और बढ़े हुए खर्च को प्रोत्साहित करेगा।

Face to Face Centres





DHYEYA IAS®
most trusted since 2003

DAILY pre PARE

Current affairs summary for prelims

2 February, 2024

सुर्खियों में स्थल

भूटान

भारत की 'पड़ोसी पहले' नीति के अनुरूप, 2024-25 के लिए सहायता पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा हिस्सा भूटान को आवंटित किया गया है। 2023-24 में 2,400 करोड़ रुपये की तुलना में इस बार 2,068 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।



भूटान (राजधानी: थिम्पू)

अवस्थिति : भूटान, दक्षिण-मध्य एशिया का एक भूमि से घिरा देश, जो हिमालय की पूर्वी चोटियों पर स्थित है।

राजनितिक सीमाएँ: भूटान की सीमा भारत (दक्षिण, पूर्व और पश्चिम) और चीन (उत्तर) से लगती है।

भौतिक विशेषताएँ:

- माउंट जोमोलहारी और गंगखार पुएनसम भूटान की प्रमुख चोटियाँ हैं।
- भूटान में पारो और पुनाखा घाटियों जैसी नदियों द्वारा बनाई गई हरी-भरी घाटियाँ।
- द्रांगमे छू, संकोश और मानस नदी जैसी नदियाँ भूटान से होकर बहती हैं।

POINTS TO PONDER

- NASA (नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन) का ओसिरिस-रेक्स हाल ही में क्षुद्रग्रह बेन्नु के सात साल के मिशन के पश्चात क्या लेकर धरती पर वापस आया ? - **मिट्टी और चट्टान के नमूने (धूल का एक कनस्तर)**
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 116 के तहत "लेखानुदान" क्या है? - **भारत की संचित निधि से अनुदान का अग्रिम आवंटन**
- रूसी-जर्मन "स्पेक्ट्रम-रॉन्टजेन-गामा" (एसआरजी) वेधशाला पर कौन सा टेलीस्कोप लगा हुआ है? - **एरोसिटा**
- वन स्टॉप सेंटर योजना भारत सरकार के किस मंत्रालय के तहत बनाई गई है? - **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय**
- मार्तंड मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है और कहाँ स्थित है ? - **सूर्य देव (सूर्य) ,जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग ज़िले में स्थित है**

Face to Face Centres

DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR: 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR: 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029



dhyeyaias.com